मुस्लिम सियासत की भावी पटकथा लिखेंगे उपचुनाव

अखिलेश वाजपेयी

प्रदेश की सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाले जिले रामपुर की रामपुर विधानसभा सीट के मतदाता आजम खां के साथ अब भी पहले की तरह मजबूती से खड़े हैं या नहीं? पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में श्रद्धा हत्याकांड जैसी घटनाओं ने एक दशक पहले हुए मुजफ्फरनगर दंगे के घावों को लोगों के दिल व दिमाग में फिर ताजा कर दिया है या नहीं? कारण, मुजफ्फरनगर दंगे की पृष्ठभूमि भी हूबहू न सही लेकिन इसी तरह की मानसिकता को लेकर घटी घटना थी।

ये ऐसे सवाल हैं जो उत्तर प्रदेश में तीन सीटों पर हुए उपचुनाव के बाद उठ रहे हैं। इन उपचुनाव की सीटें भले ही गिनती की तीन हों लेकिन समीकरणों के मद्देनजर इनके नतीजे पार्टी व प्रत्याशी की जीत-हार से ज्यादा प्रदेश में मुस्लिम राजनीति के भविष्य की भूमिका तय करते नजर आ रहे हैं। तीनों सीटों के सियासी सरोकार प्रदेश की सियासत के लिहाज से काफी गहरे और विस्तार लिए हैं, जो एक तरह से प्रदेश में बीते चार दशक की राजनीति का प्रतीक बनकर उभरे हैं। इनमें जातीय समीकरण भी महत्वपूर्ण दिख रहे हैं और हिंदुत्व की राजनीति के भी नए आयाम छिपे नजर आ रहे हैं। लोकसभा की मैनपुरी सीट स्व. मुलायम सिंह यादव की विरासत एवं सियासत से जुड़ी होने के कारण यहां का परिणाम यादव परिवार की अपने गढ़ में ताकत का पैमाना बन गई है। पर, इससे ज्यादा इस सीट के नतीजे की प्रासंगिकता समाजवादी पार्टी की जातीय गोलबंदी या पिछड़ों पर पकड़ की कसौटी से जुड़ी दिख रही है। वहीं विधानसभा की रामपुर सीट सपा के प्रमुख मुस्लिम चेहरे आजम खां के अस्तित्व से जुड़ी होने के साथ पार्टी की मुस्लिमों पर पकड़ के पैमाने का भी प्रतीक बन गई है। खतौली सीट जिस पर सपा गठबंधन में शामिल राष्ट्रीय लोकदल का उम्मीदवार लड़ रहा है उसका मुजफ्फरनगर जिले में होना ही अपने आप में सियासी सरोकारों को विस्तार दे रहा है। मुजफ्फरनगर दंगे के समय तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव एवं आजम खां का रवैया भाजपा के लिए समाजवादी पार्टी पर हमले का मुख्य हथियार बन गया था। इस दंगे ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे प्रदेश में हिंदुओं के भाजपा के पक्ष में गोलबंदी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। रामपुर प्रदेश का सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला जिला है। जिस रामपुर सीट पर चुनाव हो रहा है वहां के लगभग पौने चार लाख मतदाताओं में आधे से ज्यादा मुस्लिम हैं। जाहिर है कि इन उप चुनावों के नतीजे जीत हार से ज्यादा प्रदेश की मुस्लिम सियासत की दिशा तय करते दिख रहे हैं। इन दो सीटों के नतीजे 2024 के मद्देनजर तो प्रदेश के भविष्य के सियासी समीकरणों की भूमिका तय ही करेंगे, भाजपा या सपा के लिए मनोवैज्ञानिक बढ़त दिलाने या चुनौती बढ़ाने वाले भी होंगे। इन दो सीटों के चुनाव परिणाम प्रदेश की लगभग 19 प्रतिशत मुस्लिम आबादी की भविष्य की राजनीति के लिए एक तरह से उत्प्रेरक की भूमिका भी निभा सकते हैं।

राजनीतिक विश्लेषक प्रो. ए.पी. तिवारी कहते हैं कि इन चुनावों में किसी भी सीट पर बसपा और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। मुकाबला सीधा सपा बनाम भाजपा है। ऐसे में नतीजों से यह बात स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगी कि वर्तमान परिस्थितियों में मुस्लिम मतदाता के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। वह पूरी एकजुटता से सपा के साथ खड़ा है या भाजपा की कल्याणकारी योजनाओं ने मुसलमानों के बीच भी एक ऐसा वर्ग बनाना शुरू कर दिया है जो मोदी योगी के कामकाज के बाद हिंदुत्ववादी पार्टी कही जाने वाली भाजपा के बारे में भी सोचने लगा है। भले ही यह प्रतिशत अभी कम हो लेकिन इससे संकेत मिलेगा कि वह भविष्य के लिए किसी अन्य विकल्प के बारे में भी सोच रहा है। प्रो. तिवारी की बात सही है। तीन दशक से सपा के मुस्लिम सियासत के चेहरे आजम खां पर इस समय कानून का शिकंजा कसा हुआ है। उनकी विधानसभा सदस्यता भी रद्द हो चुकी है। ऐसे में रामपुर का नतीजा मुस्लिम मन का संकेत माना जा रहा है, जो बताएगा कि आजम पर लगे आरोपों ने मुसलमानों के बीच उनकी प्रासंगिकता को कमजोर कर दिया है या उनकी वही पकड़-पहुंच बनी हुई है जिसके दम पर उनका रामपुर सीट पर चार दशक से ज्यादा वक्त से दबदबा चला आ रहा है।

संसद सत्र से जनता को हैं बड़ी उम्मीदें

ललित गर्ग

लोकतंत्र में सफलता की कसौटी है- संसद की कार्यवाही का निर्विघ्न संचालित होना। संसद के शीतकालीन सत्र शुरू होने से पूर्व ही हंगामा होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। यह कोई नई-अनोखी बात नहीं है। क्योंकि समूचे विपक्ष ने इस सत्र को हंगामेदार करने की ठान ली है। जहां तक महंगाई, बेरोजगारी, चीन सीमा, सरकारी प्रतिष्ठानों एवं एजेन्सियों के कथित दुरुपयोग, कॉलेजियम जैसे मुद्दों को उठाने एवं इन विषयों पर सरकार से जवाब मांगने का प्रश्न है, यह स्वस्थ एवं जागरूक लोकतंत्र की निशानी है। लेकिन इन्हीं मुद्दों को आधार बनाकर जहां संसद की कार्यवाई को बाधित करने की स्थितियां हैं, यह अलोकतांत्रिक है, अमर्यादित हैं। शीतकालीन सत्र लोकतांत्रिक समझौते के साथ समझ को विकसित करने का उदाहरण बने, यह अपेक्षित है। समझौते में शर्तें व दबाव होते हैं जबकि समझ नैसर्गिक होती है। इन्हीं दो स्थितियों में जीवन का संचालन होता है और इन्हीं से राष्ट्र, समाज और लोकतंत्र का संचालन भी होता है।

लोकसभा के उपनेता एवं रक्षामंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने यह संकेत दिया कि संसद के मौजूदा सत्र में महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण जैसे विषय उसकी प्राथमिकता में होंगे। यह तो सर्वविदित है कि विपक्ष गत कुछ समय की कतिपय राजनीतिक घटनाओं से उत्साहित एवं आक्रामक हुआ है। इन्हीं बुलन्द हुए हौसलों में विपक्ष की तरफ से संसद में जिन मुद्दों पर सरकार को कठघरे में खड़ा करने की जहां कोशिश होगी, वहां सत्तापक्ष को इन विषयों पर विपक्ष की ओर से उठाए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तत्पर रहना चाहिए। विपक्ष को यह आभास कराना ही चाहिए कि उसका उद्देश्य अपने सवालों के जवाब पाना है, न कि हंगामा कर सदन की कार्यवाही ठप करना। सत्तापक्ष को इसके लिए भी तत्पर रहना चाहिए कि संसद के इस सत्र में प्रस्तावित विधेयक पारित हों। ये विधेयक व्यापक विचार-विमर्श के साथ पारित होने चाहिए। जब कभी आवश्यक विधेयक संसद में अटके रह जाते हैं तो इससे कुल मिलाकर देश को नुकसान होता है। संसद में राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर व्यापक विचार-विमर्श होना चाहिए, ताकि देश को कोई दिशा मिल सके, विकास के कार्यों को गति मिल सके, लेकिन इसके स्थान पर आरोप-प्रत्यारोप अधिक होना दुर्भाग्यपूर्ण है। कई बार तो इसे लेकर गतिरोध कायम हो जाता है जो संसद के अमूल्य समय की बर्बादी है। मौजूदा माहौल में सरकार के लिए चर्चा से इनकार करना मुश्किल होगा, लेकिन विपक्ष को भी इस बात का ध्यान रखना होगा कि अधिक आक्रामक रुख अख्तियार कर वह संसद की कार्यवाही को बाधित करने तक सीमित न रह जाए। ऐसा होने से लोकतंत्र की मूल भावना पर आघात होता है। विपक्ष सौहार्दपूर्ण माहौल बनाने और सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए पहल करें एवं एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करें।

विपक्ष के तेवरों को देखते हुए यही प्रतीत हो रहा है कि वह दोनों सदनों में सरकार की घेराबंदी के किसी मौके को नहीं छोड़ना चाहेगा, ऐसी स्थितियां बनना देशहित में नहीं है। विरोध या आक्रामकता यदि देशहित के लिये, ज्वलंत मुद्दों पर एवं समस्याओं के समाधान के लिये हो तभी लाभदायी है। लोकमान्य तिलक ने कहा भी है कि -'मतभेद भुलाकर किसी विशिष्ट कार्य के लिये सारे पक्षों का एक हो जाना जिंदा राष्ट्र का लक्षण है।' राजनीति के क्षेत्र में आज सर्वाधिक चिन्तनीय विषय है- विपक्षी दलों का सत्तापक्ष के प्रति विरोध या आक्षेप-प्रत्याक्षेप करना। सत्ता पक्ष को कमजोर करने के लिये संसदीय कार्यवाई को बाधित करना और तिल का ताड़ बनाने जैसी स्थितियों से देश का वातावरण दूषित, विषाक्त और भ्रान्त बनता है।

देश की संसद को निरपेक्ष भाव एवं सकारात्मक ढंग से राष्ट्रीय परिस्थितियों का जायजा लेते हुए लोगों को राहत प्रदान करने के प्रावधानों पर चिन्तन-मंथन के लिये संचालित करना होगा। संसद केवल विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच वाद-विवाद का स्थल नहीं होती है बल्कि जन हित में फैसले करने का सबसे बड़ा मंच होती है। इसके माध्यम से ही सत्तारुढ़ सरकार की जवाबदेही और जिम्मेदारी तय होती है और जरूरत पड़ने पर जवाबतलबी भी होती है परन्तु यह भी सच है कि सत्ता और विपक्ष की संकीर्णता एवं राजनीतिक स्वार्थ देश के इस सर्वोपरि लोकतांत्रिक मंच को लाचार भी बनाते हैं जो 130 करोड़ जनता की लाचारी बन जाते हैं। कहना कठिन है कि संसद के शीतकालीन सत्र में क्या होगा, लेकिन अच्छा यह होगा कि राजनीतिक दल उन देशों की संसद में होने वाली कार्यवाही को अपना आदर्श बनाएं, जहां प्रत्येक विषय पर धीर-गंभीर एवं सार्थक बहस होती है। आखिर अपने देश में अमेरिका और ब्रिटेन की संसद की तरह से बहस क्यों नहीं हो सकती? यदि संसद में होने वाली बहस का स्तर ऊंचा उठ सके तो देश सबसे बड़े लोकतंत्र के साथ-साथ श्रेष्ठ लोकतंत्र की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ सकता है। लेकिन संसद में होने वाली बहस के गिरते स्तर के चलते उसकी गरिमा में गिरावट आ रही है और आम जनता संसदीय कार्यवाही को लेकर उत्साहित नहीं होती।

29 दिसम्बर तक चलने वाले सत्र के दौरान सरकार की तरफ से 16 विधेयक पेश करने की योजना बनाई गई है। यदि विपक्ष हंगामा करने को अपना मकसद नहीं बनाता और सत्तापक्ष उसकी ओर से उठाए गए मुद्दों को सुनने के लिए तत्पर रहता है तो संसद का यह शीतकालीन सत्र एक कामकाजी सत्र का उदाहरण बन सकता है। संसद में केवल ज्वलंत मसलों पर उपयोगी चर्चा ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि विधायी कामकाज भी सुचारू रूप से होना चाहिए। यदि संसद को अपनी उपयोगिता और महत्ता कायम रखनी है तो यह आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है कि वहां पर राष्ट्रीय महत्व के मसलों पर सार्थक चर्चा हो। यह चर्चा ऐसी होनी चाहिए, जिससे देश की जनता को कुछ दिशा एवं दृष्टि के साथ राहत मिले, नयी योजनाओं एवं विकास को गति मिले। संसद में राष्ट्रीय महत्व के प्रश्नों पर सार्थक चर्चा के लिए दोनों ही पक्षों को योगदान देना होगा। संसद सत्र के पहले सर्वदलीय बैठकों में इसके लिए हामी तो खूब भरी जाती है, लेकिन अक्सर नतीजा ढाक के तीन पात वाला ही अधिक रहता है।

संसद राज्यों की संरक्षक एवं मार्गदर्शक भी है और जब हम भारत के विभिन्न राज्यों की तरफ नजर दौड़ाते हैं तो सर्वत्र बेचैनी, समस्याओं एवं अफरातफरी का आलम देखने को मिलता है। हर बार की तरह इस बार संसद के भीतर बिखरे विपक्ष को एकजुट करने की कोशिशें हो रही हैं। यह एकजुटता अच्छी बात है, लेकिन इसकी सकारात्मकता भी जरूरी है। एक बात और, विपक्ष आक्रामक रहकर भले ही अपनी राजनीतिक बढ़त बनाने की कोशिश करे, लेकिन इसके बावजूद वह विधायी कार्य में कोई अड़ंगा न डाले। किसी भी तौर पर यह भविष्य की नजीर नहीं बननी चाहिए क्योंकि एक व्यक्ति की हिमाकत पूरे लोकतन्त्र को प्रदूषित नहीं कर सकती। हमारी संसद तभी लोकतन्त्र में सर्वोच्च कहलाती है जब यह अपने ही बनाये गये नियमों का शुचिता, अनुशासन एवं संयम के साथ पालन करती है। अगर हम संसद में बैठे राजनीतिक दलों की हालत देखें तो वह भी बहुत निराशा पैदा करने वाली लगती है। कहने को कांग्रेस विपक्षी पार्टी है मगर जिन राज्यों में वह सत्ता में है उनमें आपस में ही इसमें सिर फुटव्वल का वातावरण बना हुआ है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान में होने के बावजूद अशोक गहलोत एवं सचिन पायलेट के बीच एक दूसरे को पछाड़ने का संघर्ष लगातार चल रहा है। जो पार्टी को नहीं जोड़ पा रहे हैं, वे भारत को क्या जोड़ेंगे? अन्य विपक्षी दलों में ही ऐसी स्थितियां देखने को मिलती हैं। लेकिन इन विपक्षी दलों के कारण कई बार संसद में हंगामा ही अधिक होता है और काम कम। यह सिलसिला तब तक कायम रहेगा, जब तक सत्तापक्ष और विपक्ष यह नहीं समझते कि संसद सार्थक संवाद का मंच है, न कि हल्ला एवं हंगामा करने का स्थान।

भारतीय ज्ञान परंपरा....

सुबालोपनिषद् (भाग-08)

गतांक से आगे...

आकाश जिसका शरीर है, जो आकाश में संचरित होता है; पर आकाश जिसे नहीं जानता। मन जिसका शरीर है, जो मन में संचरित होता है; पर मन जिसे नहीं जानता। बुद्धि जिसका शरीर है, जो बुद्धि में संचरित होता है; पर बुद्धि जिसे नहीं जानती। अहंकार जिसका शरीर है, जो अहंकार में संचरित होता है; पर अहंकार जिसे नहीं जानता। चित्त जिसका शरीर है, जो चित्त में संचरित होता है; पर चित्त जिसे नहीं जानता। अव्यक्त जिसका शरीर है, जो अव्यक्त में सञ्चरित होता है; पर अव्यक्त जिसे नहीं जानता।

अक्षर जिसका शरीर है, जो अक्षर में संचरित होता है; पर अक्षर जिसे नहीं जानता। मृत्यु जिसका शरीर है, जो मृत्यु में संचरित होता है; पर मृत्यु जिसे नहीं जानती, वे सर्वभूतों के अन्तरात्मा, विनष्ट पाप वाले, एक, दिव्य, देव, नारायण हैं।

यह विद्या (नारायण ने) अपान्तरतम नामक ब्राह्मण (अति प्राचीन काल के सिद्ध ब्राह्मण) को दी थी। अपान्तरतम ने ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने घोराङ्गिरस को, घोराङ्गिरस ने रैक्व को, रैक्व ने राम को और राम ने समस्त भूतों को प्रदान की। इस प्रकार यह निर्वाण का अनुशासन है, वेद का अनुशासन है और वेद की शिक्षा है।

सभी शरीरों के अन्दर हृदय रूपी गुहा में यह शुद्ध आत्मा निवास करता है। शरीर तो मेद, मांस और रक्त से अभिपूरित है, जो अत्यन्त नश्वर और चित्रविचित्र (चित्रस्थ दीवार) के समान गन्धर्व नगर तुल्य, केले के गर्भ की तरह निस्सार, जल के बुलबुले की तरह चञ्चल है; किन्तु उससे परे रहने वाला आत्मा अचिन्त्यरूप, दिव्य, प्रकाशवान, असङ्ग, शुद्ध, तेज: स्वरूप, अरूप, सर्वेश्वर, अचिन्त्य और अशरीर है।

हृदय रूपी गुहा में निवास करने वाला वह (आत्मा) अमृत और देदीप्यमान है। विद्वान् उसको आनन्दरूप में देखते हैं और उसमें विलय हो जाने के पश्चात् उससे भिन्न कुछ भी नहीं देखते।

इसके पश्चात् रैक्व ने घोराङ्गिरस से प्रश्न किया हे भगवन्! ये समस्त पदार्थ किसमें अस्त होते हैं ? (यह सुनकर) घोराङ्गिरस ने रैक्व को उत्तर दिया जो पदार्थ चक्षु के प्रति प्राप्त (प्रकट) होते हैं (दिखाई देते हैं), वे चक्षु (अपने अन्तर्यामी) में ही अस्त हो जाते हैं। जो द्रष्टव्य पदार्थ आदित्य के प्रति प्रकट होता है, वह आदित्य में ही विलीन हो जाता है। जो आदित्य, विराजा (सुषुम्ना नामक नाड़ी का ही एक नाम) के प्रति प्रकट होता है।

क्रमशः...

अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस आज

भ्रष्टाचार सबसे जटिल सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक घटनाओं में से एक है, जिसने दुनिया के सभी देशों को प्रभावित किया है। हम हर साल 9 दिसंबर को भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरुकता फैलाने के लिए अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाते हैं।

भ्रष्टाचार से सम्बंधित विस्तृत जानकारी जानने से पूर्व सबसे पहले यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि भ्रष्टाचार है क्या। आम शब्दों में कहें तो भ्रष्टाचार का मतलब है कि कानून व नैतिक मूल्यों की उपेक्षा करके किसी जायज या नाजायज काम को करने के लिए दिया जाने वाला अनुचित लाभ। यह लाभ आर्थिक रूप में हो सकता है जिसे रिश्वत कहते हैं या किसी और तरह से भी हो सकता है।

अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस का इतिहास 31 अक्टूबर 2003 से शुरू होता है, जब महासभा ने भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन को अपनाया था। तब से ड्रग्स एंड क्राइम (यूएनओडीसी) पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय को राज्यों के दलों के सम्मेलन के सम्मेलन के लिए सचिवालय के रूप में नामित किया गया था (संकल्प 58/4)। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने तब 9 दिसंबर को भ्रष्टाचार-विरोधी दिवस के रूप में

नामित किया था, जबकि सम्मेलन दिसंबर 2005 में लागू हुआ था। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और संपूर्ण वैश्विक समुदाय भ्रष्टाचार-विरोधी प्रथाओं के बारे में जागरुकता पैदा करने के लिए मुख्य अग्रणी हैं।

अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस का महत्व विश्व स्तर पर कदाचार के बारे में पैरोकार करना और यह बताना है कि किसी को इससे कैसे और क्यों बचना चाहिए। ये दिन भी भ्रष्टाचार-रोधी समूहों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो इस कदाचार के प्रति जागरूकता फैलाते हैं और अपने कार्यस्थल पर भ्रष्टाचार से बचने के साधनों और तरीकों को साझा करते हैं। लोकतांत्रिक संस्थाओं की नींव को बचाने के लिए भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी होने से रोकने की आवश्यकता है क्योंकि भ्रष्टाचार कानून के शासन को झुकाकर चुनावी प्रक्रियाओं को विकृत करता है। भ्रष्टाचार कई मायनों में देश के आर्थिक विकास को भी प्रभावित करता है।

संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार, हर साल 1 ट्रिलियन डॉलर का भुगतान रिश्वत के रूप में किया जा रहा है, जबकि यूएसडी 2.6 ट्रिलियन को भ्रष्ट उपायों के कारण चुराया गया है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अनुसार, यह अनुमान लगाया जाता है कि विकासशील देशों में भ्रष्टाचार के कारण 10 गुना धनराशि खो गई है, निधियों का अन्यथा उनकी आधिकारिक विकासात्मक सहायता में उपयोग किया जाएगा।

अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस की थीम है, यूनाइटेड अगेंस्ट करप्शन जो सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक के रूप में भ्रष्टाचार पर केंद्रित है। यह 2030 एजेंडा का समर्थन करना जारी रखेगा, जो अभियान की रीढ़ है, यही नहीं इस अभियान में एक युवा घटक भी होगा। भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के लिए युवाओं को न्याय के लिए जुटाना और सशक्त बनाना प्रमुख है।

केजरीवाल की सियासत से कांग्रेस दरकिनार

अतुल सिन्हा

दिल्ली की सियासी हवा बदली बदली सी है। अरविंद केजरीवाल ने नतीजों के बाद अब राजनीतिक बयानबाजियों से बचते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहयोग से दिल्ली के विकास की बात की है। चुनावी रणनीति के तहत बेशक उनके निशाने पर भाजपा रहती आई हो, तमाम सवालों पर उप राज्यपाल से टकराव की खबरें भी सतह पर आती रही हों, लेकिन उन्हें भी पता है कि दिल्ली सिर्फ एक केन्द्र शासित प्रदेश नहीं है, देश की राजधानी भी है और केंद्र की मदद के बगैर उनकी सरकार चाहकर भी कोई खास बदलाव नहीं कर सकती। उनकी अपनी सीमाएं हैं और सियासत का मतलब सिर्फ चुनावी बयानबाजी होती है।

दरअसल, केजरीवाल अब इस फार्मूले को समझ चुके हैं। इन नतीजों ने ये भी साबित किया है कि मनीष सिसोदिया, सत्येन्द्र जैन, कैलाश गहलोत और गोपाल राय के क्षेत्रों में आखिर भाजपा का अभियान कैसे रंग लाया? सत्येन्द्र जैन के जेल जाने और वहां से लगातार जारी होने वाले वीडियो ने कितना असर डाला, साथ ही सिसोदिया के खिलाफ चले अभियानों ने क्या गुल खिलाया।

इन नेताओं के इलाकों में कैसे भाजपा ने अपना परचम लहराया और कुल मिलाकर देखें तो भाजपा के वोट प्रतिशत में कैसे और क्यों करीब साढ़े तीन फीसदी का इजाफा हो गया।

आंकलन करना होगा और गणित समझना होगा अगर कुछ देर के लिए एग्जिट पोल के नतीजों

पर गौर करें तो ये साफ हो जाता है कि जिस तरह आप के बंपर जीत और भाजपा की बुरी तरह हार की भविष्यवाणियां की गई थी, वह गलत साबित हुई। बेशक आप को बहुमत मिला लेकिन ऐसी तमाम सीटें हैं जहां जीत का अंतर बहुत ही कम रहा है और भाजपा ने कांटे की टक्कर दी है।

भाजपा और आप के इस खेल में कांग्रेस लगातार हाशिए पर खिसकती जा रही है। चाहे नगर निगम के चुनाव हों या विधानसभाओं के, कांग्रेस के लिए आम आदमी पार्टी एक बड़ी मुसीबत तो बन ही चुकी है, वहीं भाजपा के लिए ज्यादातर जगहों में इसकी मौजूदगी फायदेमंद साबित होती दिखती है।

आखिर क्या है कांग्रेस की हालत?

राहुल गांधी बेशक अपनी यात्रा से भारत को जोड़ने का दावा कर रहे हों, देश की नब्ज को टटोलने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन अभी उनकी इस यात्रा को कहीं से भी पार्टी का फायदा होता नहीं दिख रहा। अपनी निजी छवि बनाने की उनकी ये कोशिश सियासी तौर पर आने वाले दिनों में कितना असर दिखाएगी, यह तो 2024 के चुनावों में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल उसका नतीजा कहीं नजर नहीं आ रहा।

वैसे भी गुजरात या दिल्ली में कांग्रेस ने पहले ही हथियार डाल रखे हैं और हिमाचल में अलग वह कांटे की टक्कर में है तो यह हिमाचल की जनता की मजबूरी कह सकते हैं और जयराम ठाकुर के गिरते ग्राफ का असर या फिर वहां का 'सियासी रिवाज'। लेकिन दिल्ली के नतीजे एक ऐसे मजबूत विकल्प और मजबूत विपक्ष का संकेत देते हैं जो कहीं न कहीं कांग्रेस के लिए एक राष्ट्रव्यापी खतरे के अंदेशे से भरा हुआ लगता है।

आप को भाजपा की बी टीम बताने वाली पार्टियां ये मानती रही हैं कि केजरीवाल कहीं न कहीं भाजपा की ही उपज हैं और उन्हें बढ़ाने के पीछे भाजपा की दूरगामी रणनीति है ताकि कांग्रेस को खत्म किया जा सके। लेकिन इन सियासी अटकलों के बावजूद ये देखने वाली बात है कि आखिर जनता का मूड क्या है और कैसे वह एक बेहतर विकल्प की तलाश में बेचैन है। उसे वह विकल्प आम आदमी पार्टी के रूप में दिखाई दे रहा है। उसे लगता है कि केजरीवाल की बातों में दम है और कम से कम दिल्ली की जनता को पिछले सात आठ सालों में केजरीवाल सरकार ने जो सहूलियत दी हैं, वह किसी सरकार ने नहीं दीं।

मुफ्त और सस्ती बिजली, मुफ्त इलाज और बेहतर अस्पताल और मोहल्ला क्लिनिक के साथ सरकारी स्कूलों के कायाकल्प और महिलाओं को बसों में मुफ्त सफर की सुविधा देकर केजरीवाल ने लोगों का दिल जीता है। बेशक आबकारी घोटाला या शराब की उनकी नीति ने उन्हें जरूर कठघरे में खड़ा किया हो लेकिन जनता ने उन्हें कम से कम नगर निगम में भाजपा से बीस ही माना है।

ये अलग सवाल है कि अब वो जिस कूड़े के पहाड़ को हटाने के नाम पर, यमुना की सफाई के नाम पर और एक स्वच्छ दिल्ली देने के नाम पर वह चुनाव जीते हैं, उसे व्यावहारिक तौर पर वह कैसे पूरा करते हैं। लेकिन अब तक प्रदूषण कम करने को लेकर की गई उनकी कोशिशें या जनता को दी जाने वाली अन्य सहूलियतों का ही असर है कि उन्हें सीधे तौर पर उसका फायदा मिला है।

जाहिर है चुनौतियां तमाम हैं, और भाजपा के साथ उनका सियासी टकराव भी उनके लिए इस खेल का हिस्सा बना रहेगा, उपराज्यपाल के साथ नए समीकरणों में उनके रिश्तों पर भी नजर बनी रहेगी, लेकिन ये तय है कि आम आदमी पार्टी ने जनता की नजर में खुद को एक मजबूत विकल्प के तौर पर पेश कर दिया है। बाकी तो सियासत है, चलती रहेगी।

गांधी आज

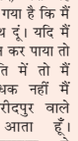

चितरंजनदास के निधन पर

पण्डित मोतीलाल नेहरू तथा महाराष्ट्र के अनुशासनबद्ध, दिग्गज नेताओं के साथ मिलकर उन्होंने शून्यवत् स्वराज्य दल को एक महान् और वर्धमान दल बना लिया और ऐसा करके उन्होंने अपनी संकल्पशक्ति, मौलिकता, साधन बाहुल्य और किसी वस्तु को अच्छा मान लेने के बाद फिर परिणाम को चिन्ता न करने आदि गुणों का परिचय दिया। फलस्वरूप आज हम स्वराज्य दल को एक ठोस और सुचारु रूप से अनुशासनबद्ध संगठन के रूप में देखते हैं। कौंसिल-प्रवेश के सम्बन्ध में मेरा उनसे मतभेद था और है। पर मैंने सरकार का काम कठिन बनाने और पग-पग पर उसके काम का अनौचित्य दिखाने के एक साधन के रूप में कौंसिल प्रवेश को उपयोगिता से कभी इनकार नहीं किया। कौंसिलों में इस दल ने जो काम किया उसके महत्त्व से कोई इनकार नहीं कर सकता और उसका श्रेय मुख्यत: देशबन्धु को ही है। मैंने हर चीज पर खूब सोच-विचार करके ही उनके साथ समझौता किया था। तब से मैंने उस दल की यथाशक्ति सहायता की है। अब उसके नेता स्वर्गवास के बाद, मेरा यह दोहरा कर्तव्य हो गया है कि मैं उस दल का साथ दूं। यदि मैं उसकी सहायता न कर पाया तो भी उसकी प्रगति में तो मैं किसी तरह बाधक नहीं मैं फिर उनके फरीदपुर वाले भाषण पर आता हूँ। स्थानापन्न वाइसराय ने श्रीमती बासन्ती देवी दास के नाम शोक सन्देश भेजा है। राष्ट्र वाइसराय महोदय की शिष्टता की कद्र करेगा। आंग्ल-भारतीय पत्रों ने स्वर्गीय देशबन्धु की स्मृति में जो उनका यशोगान किया है। मालूम होता है कि फरीदपुर वाले भाषण की खरी सत्यनिष्ठा की भावना ने अंग्रेजी के दिलपर अच्छा असर डाला है।

क्रमशः...